P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4* July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और भारत की चिंताएं : एक विश्लेषण

वीरेन्द्र चावरे
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्राशसन अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन, म.प्र

सारांश

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) की परिकल्पना 1950 के दशक में गई थी, लेकिन पिछले दशकों तक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रहने के कारण इस प्रकार की परियोजना पर विचार नहीं हो सका। इस परियोजना को प्रारंभ करने का विचार पुनः चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के निर्माण कार्य के साथ ही प्रारंभ हो गया था जो वर्ष 2002 में पूर्ण हुआ तथा जिसकी शुरूआत वर्ष 1998 में की गई थी। इस कार्य के पश्चात् चीन की शी जिनपिंग सरकार ने वर्ष 2014 में चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की अधिकारिक रूप से घोषणा कर दी। इस परियोजना के माध्यम से चीन ने पाकिस्तान में विभिन्न विकास कार्यो के लिए लगभग 46 अरब डॉलर देने का समझौता किया।[1]

इस आर्थिक गलियारे का उद्देश्य रेल्वे और राजमार्गो के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण करना हैं। इस परियोजना में सड़कों, रेल्वे, पाइपलाईनों, जल विद्युत संयंत्रों, ग्वादर बंदरगाह और अन्य विकास परियोजनाओं का विकास किया जायेगा। इस परियोजना में ग्वादर बंदरगाह को इस तरह विकसित किया जा रहा हैं ताकि पाकिस्तान 19 मिलियन टन कच्चे तेल को चीन तक सीधे भेजने में सक्षम हो सकें।[2]

मुख्य शब्द : चीन–पाकिस्तान, आर्थिक गलियारा।

प्रस्तावना

चीन–पाक आर्थिक गलियारा (CPEC) चीन की एक बहुत बड़ी परियोजना हैं, जिसके अन्तर्गत 3218 किलोमीटर लंबा एक आर्थिक गलियारा तैयार किया जा रहा हैं, जो चीन के झिंझियांग प्रांत के काश्गर शहर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाईप लाइनों से जोड़ेगा।[3] प्रारंभिक रूप से इस परियोजना में 46 अरब डॉलर का निवेश चीन द्वारा किया गया हैं लेकिन वर्तमान में इस परियोजना का बजट 46 अरब डॉलर से अधिक हो गया हैं। इसे दोनों देशों ने 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भारतीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण
   करना।
2. एशिया में चीन की विस्तावरवादी नीति तथा पाकिस्तान में उसके निवेश के कारण भारतीय चिंताओं की समीक्षा करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध–पत्र में चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भ में चीन–पाक के आर्थिक व सामरिक संबंधों का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें विषय से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, लेख–आलेख तथा वेबसाईट्स आदि स्त्रोंतो से प्राप्त अध्ययन सामग्री का उपयोग अध्ययन में किया गया है।

साहित्य समीक्षा

उरोज रिज ने अपनी पुस्तक "सीपेक चाईना–पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर" 2017 में चीन–पाक के संबंधों के इतिहास के अंतर्गत इस आर्थिक गलियारे की पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया हैं। इसके साथ ही रिज ने चीन–पाक के आर्थिक गलियारे से पड़ोसी देशों को होने वाले दूरगामी लाभ का विश्लेषण किया हैं।[4]

अर्चना राठौर ने अपनी पुस्तक "चाईना–पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सीपेक)" 2017 में चीन–पाक के आर्थिक गलियारे से एशिया और

यूरोपीय देशों को होने वाले लाभ तथा चीन की विस्तारवादी नीति का विश्लेषण किया हैं। इसमें भारत के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों तथा इस गलियारे की सुरक्षा समस्या पर भी प्रकाश डाला हैं।[5]

एंड्रयू स्माल ने अपनी पुस्तक "द चाईना–पाकिस्तान एक्सिस : एशियाज न्यू जियो– पॉलिटिक्स" 2015 में बताया कि किस प्रकार बीजिंग और इस्लामाबाद इस गलियारे के माध्यम से एशिया के केन्द्र बिन्दु बन जायेंगे। इसके साथ ही अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती भूमिका और अमेरिका के एशिया भविष्य में होने वाले प्रभाव तथा आतंकवाद व परमाणु हथियार के साथ ही पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला हैं।[6]

CPEC से चीन को लाभ

CPEC 46 अरब डॉलर की बड़ी लागत से बनने वाला यह गलियारा दक्षिण एशिया के भू–राजनैतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा। इस गलियारे का उद्देश्य चीन के उत्तरी–पश्चिमी झिंझियांग प्रांत के काश्गर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह के बीच सड़कों के 3218 किलोमीटर विस्तृत सड़क व रेल नेटवर्क द्वारा संपर्क स्थापित करना तथा दूसरी ढांचागत परियोजनाओं के माध्यम दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करना। अभी तक उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार इस परियोजना को वर्ष 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया हैं। इसके परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात् चीन को ऊर्जा आयात में वर्तमान के 12000 कि.मी. लंबे रास्ते के मुकाबले छोटे मार्ग के निर्माण से कम समय व कम खर्च लगने के साथ ही कम दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे प्रतिवर्ष चीन को लाखों डॉलर की बचत होगी साथ ही चीन की हिन्द महासागर तक पहुँच भी आसान हो जायेगी जिससे चीन को मजबूत रणनीतिक स्थिति प्राप्त होगी।[7] इस परियोजना के पूर्ण होने से चीन की यूरोप तक पहुँच आसान होगी। यह भी संभावना अवश्यंभावी है कि चीन भविष्य में ग्वादर बंदरगाह को नौसैनिक अड्डे में भी बदल सकता हैं।

CPEC पाकिस्तान को आशा हैं कि इससे पाकिस्तान की अधोसंरचना को गति मिलेगी तथा जल, सौर ऊर्जा और पवन द्वारा संचालित ऊर्जा संयंत्रों के लिए 34 बिलियन डॉलर की संभावित प्राप्ति होगी जिससे पाकिस्तान में उत्पन्न गंभीर ऊर्जा संकट में कमी आयेगी या ऊर्जा की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी। भविष्य में CPEC का हिस्सा ईरान, रूस और सउदी अरब भी बन सकते हैं। इस संभावना ने इस आर्थिक गलियारे के रहस्य को और बढ़ा दिया हैं। वहीं इस समझौते में गुप्त बातें भी हैं जिनका कम हुआ हैं जिसके अंतर्गत इस सौदे के तहत चीन, पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियों की आपूर्ति भी करेगा जिससे पाकिस्तान की नौ सैनिक शक्ति अधिक बढ़ जायेगी।[8]

पाकिस्तान में चीन की रूचि केवल आर्थिक लाभ तक ही सीमित नही हैं। पूर्ण रूप से संचालित ग्वादर बंदरगाह से चीन को केवल व्यावसायिक लाभ ही नहीं होगा बल्कि इससे बड़े पैमाने पर सामरिक और भू–राजनीतिक लाभ भी होगा। हालाँकि वर्तमान में ग्वादर को केवल व्यावसायिक हितों के लिए विकसित किया जा रहा हैं लेकिन चीनी नीतियों के कारण इस बात की पूर्ण संभावना हैं कि भविष्य में इसे एक पूर्ण सुसज्जित नौसैनिक अड्डे के तौर पर विकसित किया जायेगा। जैसा कि सर्वविदित हैं ऐसी स्थिति में चीन को इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रणनीतिक लाभ मिल सकता हैं। पाकिस्तान इन दिनों चरमपंथ, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हैं। ऐसे में पाकिस्तान का इरादा इस परियोजना से ना केवल आर्थिक लाभ लेना होगा बल्कि चीन की छत्रछाया में अपनी वैश्विक छवि को सुधारना भी होगा। हालाँकि पाकिस्तान को CPEC से होने वाले अनुमानित लाभ के साथ इससे संभावित नकारात्मक प्रभावों को भी संतुलित करना होगा।[9]

पाकिस्तान को लाभ

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकास में सब कुछ सही रहा तो यह पाकिस्तान के आर्थिक विकास की दिशा में नया अध्याय बन जायेगा। इससे पाकिस्तान के आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा रोजगारों का सृजन होगा। इस गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान में नई सड़कों, रेल मार्गो एवं हवाई अड्डों आदि निर्माण होगा। रोजगार की उपलब्धता एवं आर्थिक विकास से अतिवादियों की ओर बेरोजगार युवाओं का झुकाव कम हो जायेगा।[10] इसके साथ ही अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर पाकिस्तान की निर्भरता कम होगी। पाकिस्तान भविष्य में चीन के साथ मधुर संबंध होने के कारण भारत पर कश्मीर मुद्दें पर दबाव बनाने का प्रयास कर सकेगा।

चूँकि यह गलियारा समूचे पाकिस्तान से होकर गुजरेगा अतः गलियारे के माध्यम से यहां के सभी प्रांतों की अधोसंरचना को बेहतर होने का अवसर प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारे की रूपरेखा के अनुसार इससे नई सड़कों, राजमार्गो तथा रेल मार्गो का निर्माण होगा। पाकिस्तानी आर्थिक विशेषज्ञों को ऐसी उम्मीद हैं कि चीन के इस निवेश से पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद 15 प्रतिशत तक बढ़कर 274 बिलियन डॉलर तक पहुँच जायेगा।[11]

पाकिस्तान की ठप्प पड़ी अर्थव्यवस्था का यहां के स्थानीय ऊर्जा संकट से सीधा संबंध हैं। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से नाकाम रहा हैं। इस ऊर्जा संकट को देखते हुए CPEC कुल 10500 मेगावाट की दूसरी ऊर्जा परियोजनाएं भी प्रारंभ करेगा और इन परियोजनाओं के कार्य में तेजी आयेगी ताकि इन कार्यो को वर्ष 2018 तक पूर्ण किया जा सके। इस योजना के तहत थार मरूस्थल में 6600 मेगावाट की 10 परियोजनाओं को विकसित किया जायेगा जो इस बेहद दूर–दराज के क्षेत्र को पाकिस्तान की ऊर्जा राजधानी में बदल देगा।12

यद्यपि इस गलियारे से पाकिस्तान को एक वृहत आर्थिक लाभ मिलेगा। परन्तु इसकी क्षमता और आर्थिक औचित्य को लेकर कई शंकाऐं भी हैं। साथ ही पाकिस्तान को इन दिनों अनेक आंतरिक और बाह्य राजनैतिक चुनौतियों से जुझना पड़ रहा हैं जो इस गलियारे के विकास में बाधक बन सकते हैं।[13]

भारत की चिंताएं

भारत ने इस गलियारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध माना हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या यह हैं कि यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए जायेगा जिससे यह भविष्य में पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा मजबूत करेगा। जहां एक ओर ग्वादर पाकिस्तान के दक्षिण –पश्चिम के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर तट पर स्थित हैं। पाकिस्तान का यह क्षेत्र पाकिस्तान की आजादी से ही अलगाववादी विद्रोह का शिकार हैं तथा वर्तमान में कुछ दशकों से यहां विद्रोह और अधिक बढ़ा हैं। वहीं दूसरी ओर काश्गर चीन के मुस्लिम बहुल क्षेत्र झिंझियांग में स्थित हैं।[14] यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान में उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा जो पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों के हमले की जद में आते हैं तथा पाकिस्तान के अंदर ही पंजाब, सिंध और पी.ओ.के. में लोग इसका पूर जोर विरोध कर रहें हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस आर्थिक गलियारे का निर्माण कार्य चल रहा हैं। पाकिस्तान का यह अस्थिर आंतरिक वातावरण भारत के लिए अत्यंत चिंता का विषय हैं जिसके फलस्वरूप भारत को यह चिंता सता रहीं है कि इस परियोजना के कारण भारत के आस–पास के क्षेत्र में अशांति फैलने का स्थिति बन सकती हैं। इस आर्थिक गलियारे से चीन की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थितियों पर संभावित उपस्थिति भारत की यूरेशियाई देशों तक की पहुँच को सीमित कर सकती हैं जो कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। इसके साथ ही ग्वादर बंदरगाह के निर्माण तथा इसे नौसैनिक अड्ड़े के रूप में चीन द्वारा विकसित किया जाना, चीन द्वारा भारत को घेरने की उसकी पुरानी रणनीति "मोतियों की माला" नीति का ही विस्तार प्रतीत होता हैं।[15]

यह परियोजना हिन्द महासागर में चीन को रणनीतिक मजबूती प्रदान करेगा, जिससे भारतीय हित प्रभावित होंगे। यद्यपि पाकिस्तान का आर्थिक विकास भारत के हित में ही हैं, क्योंकि एक समृद्ध, विकसित पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए पनाहगार नहीं होगा, परन्तु भारत द्वारा चीन की महत्वाकांक्षाओं पर शक करना जायज हैं, क्योंकि चीन ने इस गलियारे को लेकर "क्षेत्रीय सहयोग" को अनदेखा किया करने साथ–साथ पी.ओ.के. में भारत की संप्रभुता को भी चुनौती दी हैं।[16]

CPEC निर्माण की पूरी योजना चीन और पाकिस्तान के द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण हैं। भारतीय संसद ने कई मर्तबा सर्वानुमति से पारित संकल्पों द्वारा दोहराया हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर सहित संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग हैं। CPEC भारत द्वारा विरोध जताने के बावजूद चीन ने प्रतिबद्धता नहीं जताई कि वह पी.ओ.के. में CPEC की आस्तियों का प्रयोग भारत के विरूद्ध नहीं करेगा। पी.ओ. के. मामलें पर चीन एक तरफ तो यह कहता हैं कि पी.ओ. के., भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला हैं जिसका हल दोनों देशों को आपस में करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पी.ओ.के. में दखल दे रहा हैं। इसलिये चीन की मंशा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक ही हैं। इस आर्थिक परियोजना के माध्यम से चीन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी हैं कि वह पी.ओ.के. में स्थायी ठिकाना बनाना चाहता हैं। चीन का यह रूख पिछले कुछ वर्षो से भिन्न हैं जिसके अंतर्गत 2009 में चीन द्वारा जम्मू–कश्मीर के लोगों को नत्थी वीसा दिया जाना जबकि वह पी.ओ.के. के लोगों के संबंध में ऐसा कुछ नहीं करता हैं।[17]

CPEC से चीन, पाकिस्तान को बनायेगा अपनी कॉलोनी

वर्तमान में जो पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हैं तथा चीन की जो नीतियों हैं उस पर कई पाकिस्तानी पत्रकारों और राजनेताओं ने अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तानी संसद में एक सांसद द्वारा यह कहा गया हैं कि चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आकार ले रहा हैं। यह बात योजना और विकास पर सीनेट की स्थायी समिति के अध्यक्ष सीनेटर ताहिर मशहदी ने कही थी और उनकी मुख्य चिंता इस गलियारे के लिए पाकिस्तान द्वारा चीन से भारी कर्ज को लेकर थी। मशहदी ने चीनी हितों के अनुरूप बिजली की दरों निर्धारित करने की मांग पर एतराज जताया था।[18] ऐसे की कई CPEC के भिन्न–भिन्न मुद्दों पर पाकिस्तानी पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने सरकार से सवाल किये हैं। जिसमें इस समझौते की विभिन्न शर्तो और वित्तीय विवरण को लेकर पारदर्शिता का अभाव को चिंता सबसे बड़ा कारण माना गया हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने इस परियोजना के बजट पर कहा हैं कि उन्हें नहीं पता हैं कि 46 अरब डॉलर में से कितना कर्ज हैं, कितनी इक्विटी और कितना सामान के रूप में आना हैं। उन्होंने इस मामलें में और अधिक पारदर्शिता की मांग की हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पाकिस्तान को आर्थिक गलियारे के संभावित नकारात्मक परिणामों को लेकर आगाह किया हैं।[19]

चीन के महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड़ प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे चीन–पाक आर्थिक गलियारे से भले ही पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें हैं लेकिन इसके उलट यह परियोजना उसके आर्थिक–सामाजिक ढांचे के लिए गंभीर खतरा भी साबित हो सकती हैं। इस परियोजना के 15 वर्ष के मास्टर प्लान पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस परियोजना के चलते पाकिस्तान को चीन के वशीभूत रहना होगा। इसका मुख्य कारण इस परियोजना के करार में शामिल की गई शर्ते हैं।[20]

इस आर्थिक गलियारे के निर्माण कार्य के कारण पाकिस्तान में कार्यरत चीनी श्रमिकों, अधिकारियों और इंजीनियरों की सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना ने एक अलग डिवीजन के अंतर्गत "विशेष सेवा समूह" के 10 हजार जवान तैनात हैं। विकास की आड़ में इस परियोजना को लेकर चीन जिस तरह से पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर बलूचिस्तान का उपयोग कर रहा हैं। इससे यहां के स्थानीय लोग चिंतित हैं। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में हजारों एकड़ जमीन पट्टे पर ली हैं ताकि फसलों को उगाया जा सकें। साथ ही चीन कंपनियों को इसे निर्यात करने के लिए पाकिस्तान को स्थानीय कर भी नहीं चुकाना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान सरकार चीन को

कई ऐसे संसाधन दे रही हैं। जिससे बाद में उसे समस्या का सामना करना पड़ सकता हैं।[21]

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के सफल होने की कुँजी बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह के पास हैं और पाकिस्तान की आकांक्षा इस क्षेत्र का आर्थिक मुखिया बनने की हैं। हालाँकि बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने को लेकर उठती आवाज और इस कारण सेना के रूख को लेकर पैदा हुआ विवाद भी इस गलियारे के लिए चुनौतियां पेश कर रहा हैं। बलूचिस्तान के नागरिक चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) का विरोध कर रहे हैं। अगर यह गलियारा सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो गया तो उम्मीद हैं कि पाकिस्तान के दूसरे प्रांत के लोग अपना प्रांत छोड़कर बलूचिस्तान आकर बस जायेंगे। [22]

निष्कर्ष

पाकिस्तान ने ऐसे आर्थिक और भौगोलिक मार्ग का चयन किया हैं जिसका एजेंडा चीन हमेशा तय करेगा। यह परियोजना पाकिस्तान के लिए अनवरत संघर्ष का विषय बनेगा। यह परियोजना पाकिस्तान में चीन का निवेश हैं जिसे पाकिस्तान को ब्याज सहित चीन को लौटाना हैं। इस परियोजना से पाकिस्तान को भविष्य में कहीं लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तानी जनता की भागीदारी बिल्कुल नहीं हैं। इसमें मजदूर से लेकर इंजीनियरिंग तथा कच्चे माल से लेकर आवश्यक उपकरण सब चीन से ही आ रहे हैं।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर शिकंजा कसते हुए उसकी आर्थिक सहायता में कमी कर दी गयी। दूसरी ओर भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकी के बीज चीन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते और भी मधुर करने में लगा हैं। चीन, पाकिस्तान के विकास को बढ़ावा देकर भारत पर दबाव बढ़ाना चाहता हैं।

पिछले तीन दशकों से खस्ता हाल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को इस परियोजना से कुछ राहत मिल सकती हैं लेकिन वो भी तब जब इस परियोजना को समय पर पूरा किया जाता हैं। यदि यह परियोजना समय पर पूर्ण ना हो सकी तो इसके गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं क्योंकि इस परियोजना का बजट वर्तमान में 46 अरब डॉलर से अधिक हो गया हैं। जिस पर भारी भरकम ब्याज पाकिस्तान को दिवालिया बना सकता हैं। फिलहाल यह परियोजना समय पर पूर्ण होती हुई नहीं प्रतीत हो रही हैं इसके अनेक कारण हैं जैसे पाकिस्तान में व्याप्त भ्रष्टाचार, चरमपंथी व पारदर्शिता की कमी आदि कारण हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान का आंतरिक राजनीतिक विवाद भी इस परियोजना की मुश्किलें बढ़ा रहा हैं।

इस आर्थिक गलियारे द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र के अतिक्रमण पर भारतीय संसद और राजनेतओं को सर्वसम्मति से अपना विरोध दर्शाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सशक्त संदेश देना चाहिए। राजनेताओं की थोड़ी सी भी निष्क्रियता पी.ओ.के. के मुद्दे पर भारत की स्थिति को कमजोर कर सकती जैसा कि पूर्व में अक्साई चीन तथा तिब्बत के मामलें में हुआ। यह गलियारा भारतीय दृष्किोण से बहुत अधिक से समस्याएं पैदा करने वाला हैं इसलिये भारत समय–समय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस गलियारे का विरोध करता रहा हैं। पहला तो यह कि इस गलियारे का पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरना जो कि भविष्य में कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को और मजबूत करेगा। दूसरा चीन की अरब सागर में पहूँच जो कि भविष्य में भारतीय हितों को प्रभावित करेगी। तीसरा चीन का इस मार्ग से मध्य–पश्चिमी एशिया तथा यूरोप तक पहुँच भारतीय उत्पादों के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगी। चौथा भविष्य में किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति में चीन भारत को जल व थल मार्ग से आसानी से भारत को घेर सकेगा। पाँचवा चीन का दखल पाकिस्तान में बढ़ जाने से वहां की आंतरिक परिस्थितियां भी भारत को लगातार प्रभावित कर सकती हैं।

अंततः यही कहा जा सकता हैं कि यह परियोजना शुद्ध रूप से चीनी हितों को पूर्ण करने के साथ–साथ भारत की समस्याओं को बढ़ायेगी और भारतीय महाद्वीप में तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब जायेगी और संपूर्ण परियोजना पर चीन की साम्राज्यवादी सोच कब्जा कर लेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Urooj Riz "CPEC: China Pakistan Economic Corridor" PI Publishers, 2017*
2. *https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/21/what-china-and-pakistans-special-friendship-means/?noredirect=on&utm_term=.2d037635c1a3*
3. *https://www.thehindu.com/news/international/chinapakistan-deal-on-economic-corridor-passing-through-pok/article4743616.ece*
4. *Urooj Riz "CPEC: China Pakistan Economic Corridor" PI Publishers, 2017*
5. *Archana Rathore "China Pakistan Economic Corridor (CPEC)" Bane or Boom Lenin Media Pvt. Ltd., 2017*
6. *Andrew Small "The China Pakistan Axis: Asia's New Geopolitics" Vintage Books, 2015*
7. *India Today, 7 August 2013, Page No. 44-45*
8. *India Today, 6 May 2015, Page No. 7*
9. *India Today, 7 August 2013, Page No. 46-47*
10. *Andrew Small "The China Pakistan Axis: Asia's New Geopolitics" Vintage Books, 2015*
11. *https://www.quora.com/What-are-the-benefits-of-CPEC-to-Pakistan*
12. *https://carnegietsinghua.org/2016/12/21/benefits-and-risks-of-china-pakistan-economic-corridor-pub-66507*
13. *Archana Rathore "China Pakistan Economic Corridor (CPEC)" Bane or Boom Lenin Media Pvt. Ltd., 2017*
14. *India Today] 15 April 2015] Page No. 52-53*
15. *https://www.nytimes.com/2015/04/23/opinion/chinas-big-plunge-in-pakistan.html*
16. *https://indianexpress.com/article/opinion/columns/one-year-of-narendra-modi-government-us-versus-them/*
17. *https://carnegietsinghua.org/2016/12/21/benefits-and-risks-of-china-pakistan-economic-corridor-pub-66507*
18. *https://www.dawn.com/news/1290677*
19. *https://www.dawn.com/news/1225339*

20. *https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/cpec-could-destroy-pakistan-economy-and-society/articleshow/58722033.cms*
21. *https://www.thehindu.com/news/international/chinapakistan-deal-on-economic-corridor-passing-through-pok/article4743616.ece*
22. *http://balochistantimes.com/cpec-baloch-perspective/*